विविध नागरिक

ए डी कोशल, नयायाधिपती,के सामने।

उदे सिंह,-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य, आदि,-प्रतिवादी।

1971 की सिविल रिट संख्या 2714।

26 नवंबर 1971

पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम (1953 का IV, 1971 के हरियाणा अधिनियम XIX द्वारा संशोधित) - धारा 5(5) (जी) - पंजाब सहकारी समिति अधिनियम (1961 का XXV) - धारा 41 - पंजाब सामान्य खंड अधिनियम (1897 का X))—धारा 2(30)—किसी पंजीकृत सहकारी समिति का कर्मचारी—चाहे वह "किसी स्थानीय प्राधिकारी का पूर्णकालिक वेतनभोगी सेवक" हो—ऐसा व्यक्ति—क्या वह पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य है?

निर्णय लिया गया कि, हरियाणा राज्य में लागू पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 की धारा 5 की उप-धारा (5) के खंड (जी) के तहत, कोई भी व्यक्ति जो "किसी भी स्थानीय प्राधिकरण का पूर्णकालिक वेतनभोगी सेवक नहीं है" राज्य" पंचायत चुनाव में खड़े होने का हकदार है। इस अधिनियम में "स्थानीय प्राधिकारी" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। पंजाब जनरल क्लॉजेज एक्ट, 1897 की धारा 2(30) में दी गई इसकी परिभाषा इसकी व्याख्या को नियंत्रित करेगी। इस परिभाषा के अनुसार "स्थानीय प्राधिकारी" का अर्थ किसी नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंधन के लिए कानूनी रूप से हकदार या सरकार द्वारा सौंपा गया कोई भी प्राधिकारी है। शब्दकोष के अर्थ के अनुसार "प्राधिकरण" शब्द केवल संवैधानिक या वैधानिक प्राधिकारियों को शामिल करता है, जिन्हें कानून द्वारा शक्तियां प्रदान की जाती हैं। निजी संस्थानों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है. पंजाब सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सहकारी समिति एक निजी संस्था है और किसी क़ानून का निर्माण नहीं है। इसका पंजीकरण इसे वैधानिक संस्था नहीं बनाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसे समाज को उप-कानून बनाने की शक्ति प्रदान की जाती है और उसे राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी दी जा सकती है, लेकिन ये कारक इसे एक सार्वजनिक या वैधानिक संस्था का चरित्र नहीं प्रदान करते हैं। केवल यह तथ्य कि किसी समाज को सरकारी सहायता उपलब्ध है, यह नहीं दर्शाता है कि वह किसी नगरपालिका या स्थानीय निधि का प्रबंधन या नियंत्रण करती है। "स्थानीय निधि" शब्द का अर्थ "नगरपालिका

निधि" अभिव्यक्ति के समान अर्थ में किया जाना चाहिए और इसका अर्थ है एक निधि जो स्थानीय सरकारी इकाई से संबंधित है, एक निधि जो निहित है या उससे संबंधित है या निर्धारित या उपलब्ध है या है एक निकाय के मामलों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए जो एक स्थानीय सरकारी इकाई है। ऐसी सरकारी इकाई के पास उस फंड का नियंत्रण या प्रबंधन होना चाहिए जो अलग रखा गया है या उपलब्ध है और जिसका उपयोग या तो देश के कानून के तहत या सरकारी सौंपे गए आधार पर, उस प्राधिकरण के मामलों को प्रशासित करने के उद्देश्य से किया जाना है। एक स्थानीय सरकारी इकाई के रूप में इसकी क्षमता। एक सहकारी समिति "स्थानीय सरकारी इकाई" के रूप में कार्य नहीं करती है और ऐसी किसी भी निधि को नियंत्रित या प्रबंधित नहीं करती है जो उपलब्ध है और जिसका उपयोग ऐसी इकाई के मामलों के प्रशासन के उद्देश्य से किया जाना है। इसलिए पंजाब सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत सहकारी समिति के एक कर्मचारी को किसी भी स्थानीय प्राधिकरण का पूर्णकालिक वेतनभोगी सेवक नहीं माना जा सकता है और उसे पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 5 के उप-धारा (5) के खंड (जी) के तहत पंचायत चुनाव लड़ने से रोका नहीं जा सकता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका जिसमें प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादी क्रमांक 2 दिनांक 6 जुलाई 1971 के आदेश को रद्द करते हुए एक उत्प्रेषण रिट, या कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

याचिकाकर्ता के वकील सुरिंदर सरूप।

एच. एन. मेहतानी, सहायक महाधिवक्ता, हरियाणा, उत्तरदाताओं संख्या 1 से 3 के लिए।

पी. एस. दौलता और वी. जी. डोगरा, अधिवक्ता, उत्तरदाताओं 4 से 9 के लिए।

निर्णय

कोशल, नयायाधिपती ।—(1) याचिकाकर्ता उदे सिंह आखिरी बार वर्ष 1963-64 में तहसील और जिला रोहतक में गिझी नामक अपने गांव की ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में चुने गए थे और 6 जुलाई 1971 तक उस पद पर बने रहे। । हरियाणा राज्य (प्रतिवादी संख्या 1) द्वारा अपने नियंत्रण में विभिन्न ग्राम पंचायतों के चुनाव कराने के लिए 6 जुलाई 1971 को जारी एक कार्यक्रम के अनुसार, ग्राम गिझी की ग्राम पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल

किए जाने थे, उनकी जांच की जानी थी और स्वीकार या अस्वीकार किया जाना था जबकि मतदान अगले दिन होना था। याचिकाकर्ता और 13 अन्य (प्रतिवादी संख्या 4 से 9 सहित) ने 6 जुलाई, 1971 को श्री बलबीर सिंह, अनुभागीय अधिकारी, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, गोहाना (प्रतिवादी संख्या 2) जो कि री-टर्निंग अधिकारी थे, के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।, लेकिन प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा इस आशय की आपत्ति उठाई गई कि याचिकाकर्ता को पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम (इसके बाद पंचायत अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 6 की उप-धारा (5) के खंड (जी) के प्रावधानों के कारण चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराया गया था चूँकि वह सांपला सहकारी विपणन सोसायटी सांपला, जिला रोहतक (इसके बाद सोसायटी कहा जाएगा), लिमिटेड के वेतनभोगी प्रबंधक थे; याचिकाकर्ता के नामांकन पत्रों को उसी तारीख को प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया था जो याचिका के साथ अनुबंध "बी" के रूप में जुड़ा हुआ है और इस प्रकार चलता है:

“श्री उदे सिंह

आपका नामांकन पत्र अस्वीकार कर दिया गया है क्योंकि आप स्थानीय प्राधिकारी, यानी मार्केटिंग सोसायटी, सांपला के पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं।“

(2) चुनाव 7 जुलाई 1971 को विधिवत आयोजित किया गया था, और उसके परिणामस्वरूप, उत्तरदाताओं संख्या 4 से 9 को गिझी गांव की ग्राम पंचायत के लिए चुने गए थे।

(3) याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा प्रार्थना के समर्थन में विभिन्न आधार रखे गए थे कि ऊपर उद्धृत प्रतिवादी संख्या 2 का आदेश अवैध और शून्य था, लेकिन मोशन बेंच के समक्ष याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री सुरिंदर सरूप ने , ने उस आदेश के खिलाफ अपने हमले को केवल एक तर्क तक सीमित रखा, अर्थात्, पंजाब सहकारी सोसायटी अधिनियम (इसके बाद सोसायटी अधिनियम के रूप में संदर्भित) के तहत पंजीकृत सहकारी समिति के एक कर्मचारी को "संपूर्ण" नहीं माना जा सकता है। किसी भी स्थानीय प्राधिकारी का समय वेतनभोगी सेवक" उस अभिव्यक्ति के अर्थ के भीतर जैसा कि ऊपर उल्लिखित खंड (जी) में प्रयोग किया गया है। इसलिए, गुण-दोष के आधार पर, 'यही एकमात्र ऐसा विवाद है जिसके लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है।

(4) उत्तरदाताओं की ओर से दो प्रारंभिक मुद्दे उठाए गए हैं। पहला यह है कि याचिका खारिज करने योग्य है क्योंकि चुनाव याचिका की स्थापना के माध्यम से एक अन्य उचित उपाय याचिकाकर्ता के लिए उपलब्ध था जो इसका सहारा लेने में विफल रहा। इस मामले में प्राप्त विशेष परिस्थितियों में मेरी राय है कि इस बात में कोई दम नहीं है। इसमें कोई विवाद नहीं है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कोई याचिका, यदि वह ग्राम पंचायत के चुनाव से संबंधित प्रश्नों से संबंधित है, तो उसके किसी भी प्रावधान द्वारा वर्जित नहीं है। आम तौर पर, हालांकि, जब चुनाव याचिका के वैकल्पिक उपाय का लाभ नहीं उठाया गया हो तो यह न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग करते हुए ऐसी याचिका पर विचार करने से इनकार कर देता है। लेकिन वर्तमान मामले में जो हुआ है वह यह है कि याचिका पर न केवल विचार किया गया है बल्कि इसके लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता ने समय की बर्बादी के कारण चुनाव याचिका दायर करने का अपना उपाय खो दिया है। यदि याचिका अब इस आधार पर खारिज कर दी जाती है कि याचिकाकर्ता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों के प्रयोग के लिए इस न्यायालय में आने से पहले एक चुनाव याचिका के वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाना चाहिए था, तो वह बिना किसी उपाय के छोड़ दिया जाएगा और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह परिणाम पर्याप्त कारण है कि इस न्यायालय को इस स्तर पर याचिका को खारिज करने के लिए अपने विवेक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह दृष्टिकोण ***एल हृदय नारायण बनाम आयकर अधिकारी***[1] मामले में सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य के अनुरूप है। उस मामले में आयकर अधिनियम की धारा 35 के तहत एक आदेश एक आयकर अधिकारी द्वारा हृदय नारायण के खिलाफ दिया गया था, जिन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका में आदेश को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने याचिका पर विचार किया और इसे न केवल योग्यता के आधार पर खारिज कर दिया, बल्कि इस कारण से भी खारिज कर दिया कि हृदय नारायण ने वैकल्पिक उपाय का लाभ नहीं उठाया था जो आदेश में संशोधन के लिए याचिका के रूप में उनके लिए खुला था। अधिनियम की धारा 33-ए के तहत आयुक्त द्वारा आयकर अधिकारी की, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को एक अपील में डिवीजन बेंच द्वारा बरकरार रखा गया था। हृदय नारायण द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दूसरी अपील की गई, जिसे स्वीकार करते हुए उनके आधिपत्य ने कहा: -

"आयकर अधिनियम की धारा 35 के तहत एक आदेश अपील योग्य नहीं है। यह सच है कि आदेश को संशोधित करने के लिए आयकर आयुक्त के समक्ष याचिका दायर की जा सकती है। लेकिन हृदय नारायण ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की और उच्च न्यायालय ने उस याचिका पर विचार किया। यदि उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका पर विचार

[1] A.I.R. 1971 S.C. 33

नहीं किया होता, तो ह्रदय नारायण आयुक्त को पुनरीक्षण के लिए आवेदन दे सकते थे, क्योंकि जिस तारीख को याचिका दायर की गई थी, उस समय अधिनियम की धारा 33-ए द्वारा निर्धारित अवधि समाप्त नहीं हुई थी। हम यह मानने में असमर्थ हैं क्योंकि धारा 35 के तहत आयकर अधिकारी के आदेश को सही करने के आदेश के लिए एक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया जा सकता था, लेकिन स्थानांतरित नहीं किया गया, उच्च न्यायालय द्वारा याचिका को खारिज करना उचित होगा क्योंकि यह याचिका विचार योग्य नहीं है जिसे गुण-दोष के आधार पर सुना गया।"

(5) उस मामले के तथ्य उन तथ्यों से बिल्कुल मिलते-जुलते हैं जिनसे हमारा संबंध है और मैं यह निष्कर्ष निकालता हूं कि याचिका को इस स्तर पर खारिज करने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि यह विचारणीय नहीं है, जब इस पर न केवल विचार किया गया है और सुनवाई भी की गई है लेकिन प्रश्न में वैकल्पिक उपाय स्वयं ही कालातीत हो गया है।

(6) अब मैं दूसरी प्रारंभिक आपत्ति की ओर ध्यान आकर्षित करता हूं। इसका आशय यह है कि याचिकाकर्ता ने उत्तरदाताओं संख्या 4 से 9 के चुनाव को रद्द करने के लिए नहीं कहा है, बल्कि केवल यह प्रार्थना की है कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा उसके नामांकन पत्रों को खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया जाए, याचिका की स्वीकृति होगी याचिकाकर्ता को कोई वास्तविक राहत नहीं मिलेगी और दूसरी ओर, यह एक अप्रभावी शासनादेश जारी करने जैसा होगा जिसे न्यायालय को जारी नहीं करना चाहिए। यह आपत्ति भी बलहीन है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता ने स्पष्ट शब्दों में केवल याचिकाकर्ता के नामांकन पत्रों को खारिज करने वाले प्रतिवादी नंबर 2 के आदेश को रद्द करने के लिए सर्टिओरीरी रिट जारी करने का दावा किया है और विशेष रूप से यह प्रार्थना नहीं की है कि उत्तरदाताओं संख्या 4 से 9 के चुनाव को भी रद्द कर दिया जाए। हालाँकि, उन्होंने याचिका के पैराग्राफ 15 के खंड (सी) में प्रार्थना की है कि:

कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जो इस मामले की परिस्थितियों में माननीय न्यायालय उचित और उचित समझे, जारी किया जाएगा"

(7) इस प्रार्थना में कोई संदेह नहीं है कि यह सामान्य शब्दों में निहित है, लेकिन इस न्यायालय द्वारा रिट जारी करने के रास्ते में कोई बाधा नहीं है, जिसे मामले की परिस्थितियों के अनुसार कहा जाता है। इस संबंध में ***चरणजीत लाई चौधरी बनाम भारत संघ और अन्य***[2] का संदर्भ दिया जा

[2]) A.I.R. 1951 S.C. 41(53)

सकता है, जिसमें उनके आधिपत्य ने देखा कि संविधान के अनुच्छेद 32 ने उन्हें अत्यावश्यकताओं के अनुरूप अपने रिट तैयार करने के मामले में बहुत व्यापक विवेक दिया है। विशेष मामले और उस अनुच्छेद के तहत किसी याचिका को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि उसमें उचित रिट या निर्देश की प्रार्थना नहीं की गई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट आदि जारी करने तक ही सीमित है, लेकिन फिर भी संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को प्रदत्त शक्ति निश्चित रूप से उतनी ही व्यापक है जितनी कि अनुच्छेद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई है। पहले उल्लेख किया गया है और ऐसा कोई कारण नहीं है कि उच्च न्यायालय को "विशेष मामलों की अत्यावश्यकताओं के अनुरूप" अपनी रिट नहीं बनानी चाहिए, जिसमें उचित रिट या निर्देश की प्रार्थना नहीं की गई है। इस प्रकार यदि याचिकाकर्ता को उत्तरदाताओं संख्या 4 से 9 के चुनाव को अवैध ठहराए जाने के परिणामस्वरूप रद्द करने का हकदार पाया जाता है, तो चुनाव को रद्द करने के लिए रिट जारी करना अदालत के लिए पूरी तरह से उचित होगा।

(8) अब मैं मामले के गुण-दोष पर आता हूं। पंचायत अधिनियम की धारा 6 (अब धारा 5) की उपधारा (5) के खंड (जी) में कहा गया है-

" जी * * * * * *

(5) कोई भी व्यक्ति जो सभा का सदस्य नहीं है और जो-

******

******

(छ) किसी स्थानीय प्राधिकारी या राज्य या भारत संघ का पूर्णकालिक वेतनभोगी सेवक है; या

(सी) ******

वह सरपंच या पंच के रूप में चुनाव में खड़े होने या बने रहने का हकदार होगा:

* * * * * * "

नामांकन पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि सोसायटी ऊपर दिए गए खंड (जी) के अर्थ के तहत एक "स्थानीय प्राधिकरण" थी। अभिव्यक्ति "स्थानीय प्राधिकरण" को अधिनियम में

परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन पंजाब जनरल क्लॉजेज एक्ट (इसके बाद इसे क्लॉजेज एक्ट कहा जाएगा) की धारा 2(30) इसे इस प्रकार परिभाषित करती है:

“2. इस अधिनियम में सभी पंजाब अधिनियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न हो, -

******

(30) 'स्थानीय प्राधिकरण' का अर्थ एक नगरपालिका समिति, जिला बोर्ड, बंदरगाह आयुक्तों का निकाय या अन्य प्राधिकारी होगा जो नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंधन के लिए कानूनी रूप से हकदार है, या सरकार द्वारा सौंपा गया है।

9) यह परिभाषा ऊपर दिए गए खंड (जी) में प्रयुक्त अभिव्यक्ति "स्थानीय प्राधिकारी" को नियंत्रित करेगी। यह विवादित नहीं है कि सोसायटी एक नगरपालिका समिति, जिला बोर्ड या बंदरगाह आयुक्तों का निकाय नहीं है। हालाँकि, यह उत्तरदाताओं का मामला है कि यह "नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंधन के लिए कानूनी रूप से हकदार या सरकार द्वारा सौंपा गया प्राधिकरण है।" उनकी ओर से मेरा ध्यान उनके विद्वान वकील द्वारा सोसायटी अधिनियम की धारा 2(एच), 4, 8, 24, 40, 41 और 57 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के नियम 8 की ओर आकर्षित किया गया है। आग्रह किया जाता है कि सोसायटी, जो सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सहकारी सोसायटी है, कोई व्यावसायिक उद्यम करने वाली संस्था नहीं है, बल्कि एक सरकारी विभाग है, जिसे सरकारी निधियों का नियंत्रण और प्रबंधन सौंपा गया है (जो कि विद्वान वकील के अनुसार, स्थानीय निधि हैं) और उपनियम बनाने की शक्ति रखते हैं। यह तर्क दिया जाता है कि ऐसी संस्था को क्लॉज़ अधिनियम की धारा 2(30) के अनुसार एक स्थानीय प्राधिकरण माना जाना चाहिए। उत्तरदाताओं की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि सोसायटी एक "राज्य" है जैसा कि उक्त खंड (जी) में दर्शाया गया है। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 12 पर भरोसा किया गया है जिसमें कहा गया है:

“इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, 'राज्य' में भारत की सरकार और संसद और प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल और भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के तहत सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण शामिल हैं।"

(10) यह आग्रह किया जाता है कि भले ही सोसायटी एक स्थानीय प्राधिकरण नहीं है, यह अनुच्छेद 12 में उल्लिखित "अन्य प्राधिकरणों" में से एक है।

(11) इन तर्कों के पक्ष और विपक्ष में मुझे विस्तार से तर्क दिए गए हैं और उन पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, मैंने पाया कि ये तर्क बलहीन हैं और सोसायटी को खंड (जी) के अर्थ में एक स्थानीय प्राधिकरण नहीं माना जा सकता है।

(12) निर्धारण के लिए सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि क्या सोसायटी वास्तव में एक "प्राधिकरण" है। "प्राधिकरण" शब्द को पंचायत अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है और इसलिए, इसका शब्दकोश अर्थ दिया जाना चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अभिव्यक्ति "स्थानीय प्राधिकारी" को सामान्य खंड अधिनियम (1897 का केंद्रीय अधिनियम संख्या एक्स) की धारा 3(31) द्वारा गई गई है। फिर, वह परिभाषा और खंड अधिनियम की धारा 2(30) में दी गई परिभाषा समान शर्तों में होने के कारण एक ही अर्थ में समझी जा सकती है। इसका परिणाम यह है कि खंड अधिनियम की धारा 2(30) में आने वाले शब्द "प्राधिकरण" का वही अर्थ होगा जो संविधान के अनुच्छेद 12 में उपयोग किए जाने पर इसके साथ जुड़ा हुआ है। अनुच्छेद 12 में घटित इस शब्द की व्याख्या करते हुए ***राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड बनाम मोहन लाई और अन्य***[3] मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य ने कहा:

"इसलिए, इस लेख में 'अन्य अधिकारियों' की अभिव्यक्ति की व्याख्या के लिए एजुस्डेम जेनेरिस के डॉक्टरिन को लागू नहीं किया जा सकता है।"

वेबस्टर के तीसरे नए अंतर्राष्ट्रीय शब्दकोश में दिए गए 'प्राधिकरण' शब्द का अर्थ, जो लागू हो सकता है, एक सार्वजनिक प्रशासनिक एजेंसी या निगम है जिसके पास अर्ध-सरकारी शक्तियां हैं और राजस्व उत्पादक सार्वजनिक उद्यम को प्रशासित करने के लिए अधिकृत है। 'प्राधिकरण' शब्द का यह शब्दकोश अर्थ स्पष्ट रूप से इतना व्यापक है कि इसमें क़ानून द्वारा बनाए गए सभी निकाय शामिल हैं, जिन पर सरकारी या अर्ध-सरकारी कार्यों को करने के लिए शक्तियां प्रदान की जाती हैं। 'अन्य प्राधिकरण' की अभिव्यक्ति इतनी व्यापक है कि इसमें किसी क़ानून द्वारा बनाए गए और भारत के क्षेत्र के भीतर, या भारत सरकार के नियंत्रण में कार्य करने वाले प्रत्येक प्राधिकरण को

[3] A.I.R. 1967 S.C. 1857

शामिल किया जा सकता है; और हमें उस संदर्भ में इस अर्थ को सीमित करने का कोई कारण नहीं दिखता है जिसमें संविधान के अनुच्छेद 12 में 'अन्य प्राधिकारी' शब्द का उपयोग किया गया है।"

न्यायाधीशों ने न्यायाधीश अय्यंगार की ***श्रीमती उज्जम बाई बनाम उत्तर प्रदेश राज्य***[4] , अनुच्छेद 12 में अभिव्यक्ति "अन्य प्राधिकरण" की व्याख्या के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियों पर भी भरोसा किया।:

"फिर से, अनुच्छेद 12 भारत के क्षेत्र के भीतर 'अन्य प्राधिकारियों' का संदर्भ देकर परिभाषा के अंतर्गत आने वाले प्राधिकारियों की सूची को समाप्त कर देता है, जिसे स्पष्ट रूप से सरकार और विधानमंडल या स्थानीय प्राधिकारियों के साथ ईजसडेम जेनेरिस के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। ये शब्द व्यापक आयाम के हैं और एक क़ानून के तहत बनाए गए और भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में कार्य करने वाले प्रत्येक प्राधिकरण को समझने में सक्षम हैं। इस अवशिष्ट खंड में 'प्राधिकरण' की प्रकृति का कोई लक्षण वर्णन नहीं है और परिणामस्वरूप इसमें संसद या राज्य द्वारा अधिनियमित कानूनों को प्रशासित करने के उद्देश्य से एक क़ानून के तहत स्थापित हर प्रकार के प्राधिकरण को शामिल किया जाना चाहिए, जिसमें कर्तव्य के साथ निहित अधिकार और उन कानूनों को लागू करने के लिए निर्णय लेना भी शामिल हैं।"

न्यायाधीशों द्वारा के.एस. ***राममूर्ति रेडियार बनाम मुख्य आयुक्त, पांडिचेरी***[5] मामले में उनके द्वारा की गई अनुच्छेद 12 की निम्नलिखित व्याख्या का भी संदर्भ दिया गया।

"इसके अलावा, भारत के क्षेत्र के भीतर सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकरणों में भारत के क्षेत्र के सभी प्राधिकरण शामिल हैं, चाहे वे भारत सरकार या विभिन्न राज्यों की सरकारों के नियंत्रण में हों और यहां तक कि स्वायत्त प्राधिकरण भी जो सरकार के नियंत्रण में न हों।"

(13) बहुमत का फैसला सुनाने वाले न्यायाधीश भार्गव ने जो निष्कर्ष निकाला, वह था:

"न्यायालय के ये निर्णय हमारे विचार का समर्थन करते हैं कि अनुच्छेद 12 में 'अन्य प्राधिकरण' अभिव्यक्ति में सभी संवैधानिक या वैधानिक प्राधिकरण शामिल होंगे, जिन्हें कानून द्वारा शक्तियां प्रदान की गई हैं। यह बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है कि प्रदत्त कुछ शक्तियां व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने के उद्देश्य से हो सकती हैं। संविधान के तहत, राज्य को स्वयं अनुच्छेद 19(एल)(जी) में उल्लिखित व्यापार या व्यवसाय करने का अधिकार होने की परिकल्पना की गई है। भाग IV में, राज्य को अनुच्छेद 12 के समान ही अर्थ दिया गया है और अनुच्छेद 46 में दिए गए निदेशक सिद्धांतों में से एक यह है कि राज्य लोगों के कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों

[4] A.I.R, 1962 S,C. 1621
[5] AXR. 1963 S.C. 1464

को विशेष देखभाल के साथ बढ़ावा देगा। जैसा कि अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है, राज्य में लोगों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाए गए निकायों को शामिल किया गया है। हमारे संविधान द्वारा गठित राज्य को किसी भी व्यापार या व्यवसाय को चलाने के लिए अनुच्छेद 298 के तहत विशेष रूप से सशक्त बनाया गया है। ऐसी परिस्थिति कि विद्युत आपूर्ति अधिनियम के तहत बोर्ड को व्यापार या वाणिज्य की प्रकृति की कुछ गतिविधियों को चलाने की आवश्यकता होती है, इसलिए, यह कोई संकेत नहीं देता है कि बोर्ड को अनुच्छेद 12 में 'राज्य' शब्द के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए जैसा कि इसमें इस्तेमाल किया गया है। दूसरी ओर, विद्युत आपूर्ति अधिनियम में प्रावधान हैं, जो स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों में निर्देश देने की शक्ति भी शामिल है, जिसकी अवज्ञा एक आपराधिक अपराध के रूप में दंडनीय है। इन परिस्थितियों में, हम श्री देसाई द्वारा हमारे सामने यह आग्रह करने के लिए उद्धृत मामलों की जांच करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं समझते हैं कि बोर्ड को सरकार का एजेंट या साधन नहीं माना जा सकता है। बोर्ड स्पष्ट रूप से एक प्राधिकरण था जिस पर संविधान के भाग III के प्रावधान लागू थे।

(14) न्यायाधीश शाह ने एक अलग फैसले में सहमति व्यक्त की कि राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड अनुच्छेद 12 के अर्थ में "राज्य" था। न्यायाधीश के अनुसार ऐसा इसलिए था, क्योंकि बोर्ड को राज्य की कुछ संप्रभु शक्तियों के साथ क़ानून द्वारा निवेशित किया गया था। उनका आधिपत्य बहुमत के इस दृष्टिकोण से सहमत होने में असमर्थ था कि प्रत्येक संवैधानिक या वैधानिक प्राधिकारी, जिस पर कानून द्वारा शक्तियां प्रदान की गई थीं, अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर "अन्य प्राधिकारी" था। उनके आधिपत्य की राय में:

"अभिव्यक्ति 'अधिकार' का व्युत्पत्ति संबंधी अर्थ में अर्थ है एक ऐसा निकाय जिसमें आदेश देने या अंतिम निर्णय देने, या आज्ञाकारिता लागू करने, या आदेश देने और पालन कराने का कानूनी अधिकार रखने की शक्ति निहित है।"

(15) फैसले में मेरे द्वारा उद्धृत उपरोक्त टिप्पणियाँ संदेह के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती हैं कि भले ही अनुच्छेद 12 में आने वाले "अधिकार" शब्द का उपयोग उनके आधिपत्य द्वारा बहुत व्यापक अर्थ में किया गया था, लेकिन यह केवल अपनाने के लिए पाया गया था संवैधानिक या वैधानिक प्राधिकारी जिन्हें कानून द्वारा शक्तियां प्रदान की गई थीं। निहितार्थ से निजी संस्थानों को इसके दायरे से बाहर रखा गया था और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस शब्द के अर्थ को और अधिक

विस्तारित नहीं किया जा सकता है ताकि इसके दायरे में किसी भी निजी संस्थान को शामिल किया जा सके।

(16) ***प्रागा टूल्स कॉर्पोरेशन बनाम श्री सी. ए. इमानुअल और अन्य***[6] , उसी परिणाम की ओर ले जाता है। उस मामले में सवाल यह था कि क्या कंपनी अधिनियम के तहत निगमित कंपनी के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा परमादेश जारी किया जा सकता है। विचाराधीन कंपनी प्रागा टूल्स कॉरपोरेशन थी जिसमें केंद्र सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच भौतिक समय में क्रमशः 56 प्रतिशत और 32 प्रतिशत शेयर थे, शेष 12 प्रतिशत शेयर निजी लोगों के पास थे। सबसे बड़ी शेयरधारक होने के नाते केंद्र सरकार के पास कंपनी के निदेशकों को नामित करने की शक्ति थी। उनके आधिपत्य में यह माना गया था कि कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होने और उस अधिनियम के प्रावधानों द्वारा शासित होने के कारण कंपनी एक गैर-वैधानिक निकाय थी, जिस पर क़ानून द्वारा कोई वैधानिक या सार्वजनिक कर्तव्य नहीं लगाया गया था जिसके संबंध में प्रवर्तन की मांग की जा सकती थी। एक परमादेश के माध्यम से इस आदेश का पालन करते हुए, न्यायाधीश तुली ने ***धर्म पाल सोनी बनाम पंजाब राज्य***[7] में कहा कि सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सोसायटी भी एक गैर-वैधानिक निकाय थी, जिस पर किसी क़ानून द्वारा कोई वैधानिक या सार्वजनिक कर्तव्य नहीं लगाया गया था, जैसा कि परमादेश की रिट द्वारा लागू किया जा सकता है।

(17) मौजूदा मामले में भी सोसायटी सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक निजी संस्थान है। यह किसी क़ानून का निर्माण नहीं है। इसके शेयरधारक इसे अस्तित्व में नहीं लाने के लिए स्वतंत्र थे और इसका पंजीकरण इसे वैधानिक संस्था नहीं बनाता है। सोसायटी अधिनियम के प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम, जिन पर उत्तरदाताओं के विद्वान वकील भरोसा करते हैं, इस मुद्दे पर उनके मामले को आगे नहीं बढ़ाते हैं। सोसायटी अधिनियम की धारा 2 (एच) में केवल यह कहा गया है कि "अधिकारी" का अर्थ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, सचिव, आदि (एक सहकारी समिति का) है। धारा 4 दिन नीचे कि एक सोसायटी, जिसका उद्देश्य सहकारी सिद्धांतों के अनुसार अपने सदस्यों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है, या ऐसी सोसायटी के संचालन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से स्थापित एक सोसायटी, के तहत पंजीकृत हो सकती है। धारा 8 उन शर्तों से संबंधित है जिनके बारे में संतुष्ट होने पर रजिस्ट्रार किसी सोसायटी को

[6] 1969 (1) S.C.C. 585
[7] 1969 S..LR. 349

पंजीकृत कर सकता है। धारा 24 के अनुसार, कुछ निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए सहकारी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार आयोजित की जानी चाहिए। धारा 40 में सहकारी समितियों को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। धारा 41 किसी सहकारी समिति के धन के बोनस या लाभांश के माध्यम से विभाजन पर रोक लगाती है। धारा 57 सहकारी समितियों को बंद करने का प्रावधान करती है। सोसायटी अधिनियम के तहत बनाए गए पंजाब सहकारी सोसायटी नियम, 1963 का नियम 8 एक सहकारी सोसायटी द्वारा उप-कानून बनाने का प्रावधान करता है।

(18) इन प्रावधानों को चाहे सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से माना जाए, यह संकेत नहीं मिलता है कि सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक सहकारी समिति या तो एक सार्वजनिक या वैधानिक निकाय होगी या एक सरकारी विभाग होगी जिसे सरकारी धन सौंपा जाएगा। न ही यह कहा जा सकता है कि ऐसे समाज को व्यावसायिक गतिविधियाँ चलाने वाली संस्था नहीं माना जा सकता। ऐसे समाज को निस्संदेह उपनियम बनाने की शक्ति प्रदान की जाती है और उसे राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता भी दी जा सकती है, लेकिन ये कारक उसे एक सार्वजनिक या वैधानिक संस्था का चरित्र नहीं प्रदान कर सकते हैं।

(19) उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने विपरीत प्रस्ताव के समर्थन में कुछ अधिकारियों का हवाला दिया और अब उसकी जांच की जा सकती है। ***पी. एम. ब्रमदाथन नंबूरीपाद बनाम कोचीन देवस्वोम बोर्ड***[8] मामले में, यह माना गया कि त्रावणकोर-कोचीन हिंदू धार्मिक संस्थान अधिनियम के तहत गठित कोचीन देवस्वोम बोर्ड को संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के तहत एक स्थानीय प्राधिकरण नहीं माना जा सकता है। लेकिन यह स्पष्ट रूप से उसमें उल्लिखित "अन्य प्राधिकरण" के दायरे में आता है। यह सच है कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने में पूर्ण पीठ मुख्य रूप से इस विचार से प्रभावित थी कि कोचीन देवास्वोम बोर्ड के पास नियम, उपनियम या विनियम जारी करने की शक्ति थी, लेकिन तब वह बोर्ड एक क़ानून का निर्माण कर रहा था ताकि नियम , इसके तहत बनाए गए उपनियमों या विनियमों में कानून का बल था। मेरी राय में, यह मामला उत्तरदाताओं के लिए कोई सहायता का नहीं है, क्योंकि सोसायटी एक वैधानिक या सार्वजनिक निकाय नहीं है और इसके द्वारा बनाए गए उपनियमों को कानून नहीं माना जा सकता है या कानून का बल नहीं माना जा सकता है। मामला ***सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड और अन्य बनाम अतिरिक्त औद्योगिक न्यायाधिकरण***[9] में सर्वोच्च न्यायालय के उनके आधिपत्य के आदेश से समाप्त होता है, जिसमें

[8] A.I.R. 1956 Tra. Co. 19(F.B.).
[9] ALR. 1970 S.C. 245.

आंध्र राज्य में 25 सहकारी केंद्रीय बैंकों के उपनियम प्रदेश, आंध्र प्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी होने के नाते, कंपनी अधिनियम के तहत निगमित कंपनी के एसोसिएशन के लेखों की प्रकृति में इन शब्दों में माना जाता था:

"हम इस दलील को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में बनाए गए सहकारी समिति के उपनियमों को कानून माना जा सकता है या कानून की शक्ति प्राप्त की जा सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि, यदि कोई क़ानून किसी सरकार या अन्य प्राधिकारी को नियम बनाने की शक्ति देता है, तो इस प्रकार बनाए गए नियमों में क़ानून का बल होता है और उन्हें क़ानून के एक भाग के रूप में शामिल माना जाएगा। हालाँकि, यह सिद्धांत उस प्रकृति के उपनियमों पर लागू नहीं होता है जिसे बनाने के लिए एक सहकारी समिति को अधिनियम द्वारा अधिकार दिया गया है। अधिनियम द्वारा जिन उपनियमों पर विचार किया गया है वे केवल वे हो सकते हैं जो किसी समाज के 'आंतरिक प्रबंधन, व्यवसाय या प्रशासन' को नियंत्रित करते हैं। वे उनके द्वारा चुने गए व्यक्तियों के बीच बाध्यकारी हो सकते हैं, लेकिन उनके पास क़ानून की शक्ति नहीं है।"

(20) ***दुखूराम गुप्ता-हरि प्रसाद गुप्ता बनाम सहकारी कृषि संघ, लिमिटेड***[10] , जो इसके विपरीत एक प्रस्ताव देता है और जिस पर उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया था, उसे ***सहकारी सेंट्रल बैंक लिमिटेड और अन्य बनाम अतिरिक्त औद्योगिक न्यायाधिकरण (9) (सुप्रा)*** द्वारा खारिज कर दिया जाना चाहिए।

(21) उत्तरदाताओं के लिए निर्भरता अब ***ओछायलाल जेठालाल देसाई और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य***[11] पर थी। उस मामले में सवाल यह था कि क्या बॉम्बे कृषि उपज बाजार अधिनियम (1939 का XXII) के तहत गठित एक बाजार समिति सामान्य खंड अधिनियम की धारा 3(31) के अर्थ के तहत एक स्थानीय प्राधिकरण थी। मेरे समक्ष प्रतिवादियों के विद्वान वकील द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन करने की बात तो दूर, मामले में की गई निम्नलिखित टिप्पणियाँ याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए रुख के पक्ष में जाती हैं:

"ऐसा प्राधिकरण एक स्थानीय प्राधिकरण हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि उसके पास नगरपालिका या स्थानीय निधि का नियंत्रण या प्रबंधन हो। मोटे तौर पर, यह संभव नहीं है कि एक

[10] A.I.R. 1961 M.P. 289.
[11] 1967 Gujrat Lar Reporter 359

प्राधिकरण जो नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंधन में है, वह स्थानीय प्रशासन की इकाई नहीं होगी। इन परिस्थितियों में, हमारे निर्णय में, एक प्राधिकारी के स्थानीय प्राधिकारी होने के लिए, यह पर्याप्त नहीं है कि उसे कुछ शक्ति का प्रयोग करना चाहिए या कर्तव्य का पालन करना चाहिए, बल्कि, यह आवश्यक है कि उसे स्थानीय क्षेत्र में कुछ सरकारी कार्यों का प्रबंधन करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, किसी प्राधिकरण के स्थानीय प्राधिकरण होने के लिए यह आवश्यक है कि वह एक पूर्व-निर्धारित या परिभाषित इलाके के भीतर काम करे और उन कार्यों का निर्वहन करे जो राज्य द्वारा किए जा सकते हैं और जो कार्य स्वाभाविक रूप से सौंपे जाएंगे या इसे किसी क़ानून या किसी अन्य कानूनी दस्तावेज़ द्वारा सौंपा गया है। दूसरे शब्दों में, अभिव्यक्ति, 'प्राधिकरण' का अर्थ एक कानूनी रूप से गठित निकाय है जो स्थानीय सरकार के कार्यों का निर्वहन करता है - एक निकाय जो एक निर्दिष्ट, पूर्व निर्धारित या परिभाषित इलाके के संबंध में संपूर्ण या आंशिक सरकारी कार्यों को करने के लिए अधिकृत है। इसलिए, बाजार समिति 'स्थानीय प्राधिकरण' अभिव्यक्ति के अर्थ में एक प्राधिकरण हो सके, इसके लिए यह आवश्यक है कि उसके पास एक निर्दिष्ट इलाके के संबंध में सभी या कुछ सरकारी कार्यों को करने का अधिकार होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, अभिव्यक्ति 'अन्य प्राधिकरण' का अर्थ एक स्थानीय प्रशासनिक इकाई है और यह स्थानीय सरकार की एक प्रजाति है।“

स्पष्ट रूप से सोसायटी स्थानीय प्राधिकारी की योग्यताओं को पूरा नहीं करती जैसा कि इन टिप्पणियों में बताया गया है।

(22) ***उमेश चंद्र सिन्हा बनाम एन.एन. सिंह और अन्य***[12] , में जो उत्तरदाताओं के लिए भरोसा किया गया एक और मामला था, याचिकाकर्ता पटना मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए एक आवेदक था जो कि पटना विश्वविद्यालय के नियंत्रण में एक संस्थान है। उन्हें प्रवेश के लिए नहीं चुना गया था और उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह घोषणा करने के लिए याचिका दायर की थी कि मेडिकल पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश के लिए उक्त विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए अध्यादेश के कुछ प्रावधान असंवैधानिक थे और एक उचित मुद्दे के लिए याचिका दायर की गई थी। संबंधित प्राधिकारियों के विरुद्ध रिट लिखकर उन्हें उसके मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। पूर्ण पीठ ने माना कि विश्वविद्यालय संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के तहत एक राज्य था और ऐसा करने में यह पाया गया कि एकमात्र उचित निष्कर्ष ***राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड बनाम मोहन लाई और अन्य (3), (सुप्रा)*** में सुप्रीम कोर्ट के बहुमत के फैसले से निकाला जा सकता है। यह था कि क़ानून द्वारा निर्मित कोई भी सार्वजनिक प्राधिकरण, जिस पर कानून द्वारा शक्तियां

[12] A.I.R. 1968 Pat. 3 (F.B.)

प्रदान की गई थीं, को इस तथ्य के बावजूद एक राज्य माना जाना चाहिए कि उस प्राधिकरण के कार्य संप्रभु कार्य थे या गैर- संप्रभु कार्य जैसे शिक्षा का प्रसार, आदि। मैं नहीं देखता कि यह मामला उत्तरदाताओं के मुद्दे को कैसे आगे बढ़ाता है। जैसा कि मैंने पहले ही संकेत दिया है, सोसायटी किसी क़ानून का निर्माण नहीं कर रही है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित और पटना मामले में पूर्ण पीठ द्वारा लागू किए गए मानदंड उनके लिए कोई सहायता नहीं कर सकते हैं।

(23) प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत एक अन्य मामला ***मोहम्मद सिंह बनाम भारत संघ***[13] था, जिसमें तथ्य ये थे। लॉरेंस स्कूल, सनावर, मूल रूप से भारत सरकार द्वारा स्वामित्व, नियंत्रित और प्रबंधित किया गया था। 26 जून, 1952 को, शिक्षा मंत्रालय में सरकार ने सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत गठित एक सोसायटी के माध्यम से स्कूल का प्रशासन चलाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। एसोसिएशन का ज्ञापन और सोसायटी के नियम और विनियम संयुक्त स्टॉक कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास दाखिल करने से पहले सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना था। सोसायटी के पंजीकरण पर स्कूल का प्रशासन सोसायटी में निहित होना था। सरकार की मंजूरी के साथ सोसायटी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और विनियम संयुक्त स्टॉक कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास दाखिल किए गए। सोसायटी के मामलों का प्रबंधन एक बोर्ड को सौंपा गया था। स्कूल के कर्मचारी सरकारी सेवक नहीं रहे और बोर्ड के कर्मचारी बन गए, बशर्ते कि वे बोर्ड की सेवा करने के लिए सहमत हों और बोर्ड उन्हें जारी रखने के लिए सहमत हो। स्कूल की संपत्ति भी बोर्ड को हस्तांतरित कर दी गई। याचिकाकर्ता, जो मूल रूप से स्कूल के स्थायी स्टाफ में था, को बोर्ड द्वारा बरकरार रखा गया। बाद में विनियमों के संदर्भ में बोर्ड की मंजूरी के साथ हेडमास्टर द्वारा उचित नोटिस के बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 311 और 226 के तहत एक याचिका में कहा गया कि सोसायटी और बोर्ड सरकार के विभाग नहीं हैं। लेकिन यह तर्क दिया गया कि अभी भी स्कूल के हेडमास्टर के आदेश को रद्द करने के लिए एक रिट जारी की जा सकती है जिसके द्वारा उन्होंने याचिकाकर्ता की सेवाओं को समाप्त कर दिया, क्योंकि समाज पर लगाए गए वैधानिक दायित्वों का उल्लंघन किया गया था, जो एक वैधानिक निकाय था। यह आग्रह किया गया कि संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रयोजन के लिए समाज को "राज्य" माना जा सकता है, जो भारत के क्षेत्र के भीतर या सरकार के नियंत्रण में एक "प्राधिकरण" है। यह तर्क दिया गया कि स्कूल के नियम वैधानिक हैं, इन्हें सोसायटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 2 के अनुसार तैयार किया गया है, और इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 13(3) में दी गई "कानून" की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। न्यायाधीश जगजीत सिंह और एस.एन. शंकर की खंडपीठ ने यह निर्णय दिया कि स्कूल को

[13] A.I.R. 1969 Delhi 170.

नियंत्रित करने और प्रशासन करने वाली सोसायटी को एक क़ानून के तहत बनाई गई "प्राधिकरण" के रूप में माना जा सकता है, जिसे कानून द्वारा कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं और जो भारत के क्षेत्र के भीतर कार्य किया। जो निष्कर्ष निकला, उसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि वह कोई सामान्य सिद्धांत निर्धारित करता है, लेकिन इसे उस मामले के विशेष तथ्यों तक ही सीमित माना जाना चाहिए, जिसमें स्कूल, सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, एक सरकारी संगठन था। हालाँकि, मामले का फैसला करने वाले विद्वान न्यायाधीशों के प्रति अत्यंत सम्मान के साथ, मैं यह दोहराने में मदद नहीं कर सकता कि स्कूल को नियंत्रित करने वाले समाज को सर्वोच्च न्यायाधीशों के आदेश के मद्देनजर एक क़ानून का निर्माण नहीं माना जा सकता है। ***प्रागा टूल्स कॉर्पोरेशन बनाम श्री सी. ए. इमानुअल और अन्य में न्यायालय (6) (सुप्रा)*** में यह भी देखा जा सकता है कि उक्त निष्कर्ष एक ओबिटर डिक्टम की प्रकृति में है और मामले का निर्णय याचिकाकर्ता के खिलाफ गया क्योंकि स्कूल के नियमों को चरित्र में वैधानिक नहीं माना गया था और न ही कानून कीबल देने की राशि थी। इसलिए, मामला उस मुद्दे के निर्णय के लिए कोई वास्तविक मार्गदर्शन नहीं देता है जिससे हम यहां संबंधित हैं।

(24) उपरोक्त चर्चा को सारांशित करने के लिए, सोसायटी को खंड अधिनियम की धारा 2(30) के अर्थ में एक "प्राधिकरण" के रूप में नहीं माना जा सकता है, जो पंचायत अधिनियम की धारा 6 के उप-धारा (5) के खंड (जी) की व्याख्या की कुंजी प्रस्तुत करता है, या संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर उस खंड के एक राज्य के रूप।

(25) दूसरी आवश्यकता जिसे किसी संस्था को क्लॉज अधिनियम की धारा 2(30) के अर्थ में स्थानीय प्राधिकरण के रूप में माना जाने से पहले पूरा किया जाना चाहिए, सोसायटी के मामले में भी कमी है। वह आवश्यकता यह है कि उसे किसी नगरपालिका या स्थानीय निधि के प्रबंधन या नियंत्रण का अधिकार होना चाहिए या सरकार द्वारा सौंपा जाना चाहिए। केवल यह तथ्य कि सोसायटी अधिनियम की धारा 41 के तहत सोसायटी को सरकारी सहायता उपलब्ध है, यह नहीं दर्शाता है कि सोसायटी किसी नगरपालिका या स्थानीय निधि का प्रबंधन या नियंत्रण करती है। उत्तरदाताओं की ओर से यह स्वीकार किया गया कि सोसायटी के फंड को नगरपालिका फंड के चरित्र में भाग लेने वाला नहीं माना जा सकता है। हालाँकि, उनके विद्वान वकील ने यह तर्क उठाया कि वे फंड "एक स्थानीय फंड" थे। प्रस्ताव के लिए ***ओछायलाल जेठालाल देसाई और अन्य बनाम गुजरात राज्य और अन्य (11) (सुप्रा)*** और ***भिखारी बेहरा बनाम एस.एम. धनपति***

बेंटिया[14] से समर्थन मांगा गया था। गुजरात का मामला उत्तरदाताओं की ओर से दिए गए प्रस्ताव के विपरीत है। जनरल क्लॉजेज एक्ट की धारा 3(31) में आने वाले शब्द "स्थानीय निधि" की व्याख्या करते हुए मियाभोय, मुख्य न्यायाधीश, जिन्होंने उस मामले में डिवीजन बेंच का फैसला सुनाया, ने कहा:

"परिस्थितियों में, हमारे निर्णय में, अभिव्यक्ति 'स्थानीय निधि' को भी अभिव्यक्ति 'नगरपालिका निधि' के समान अर्थ में समझा जाना चाहिए। इसका मतलब एक फंड होगा जो एक स्थानीय सरकारी इकाई से संबंधित है - एक फंड जो किसी स्थानीय सरकारी इकाई में निहित है या उससे संबंधित है या निर्धारित या उपलब्ध है या किसी निकाय के मामलों के लिए उपयोग किया जाना है। हमारे निर्णय में, उपरोक्त परिभाषा को पूरा करने के लिए, परिभाषा के बाद के भाग में उल्लिखित प्राधिकारी के पास उस फंड का नियंत्रण या प्रबंधन होना चाहिए जो अलग रखा गया है या उपलब्ध है और जिसका उपयोग या तो कानून के तहत किया जाना या तो स्थानीय सरकारी इकाई के रूप में अपनी क्षमता में उस प्राधिकरण के मामलों को प्रशासित करने के उद्देश्य से, सरकारी सौंपे गए आधार पर भूमि के कानून के तहत।"

उपरोक्त परीक्षण को पूरा करने के लिए, जो कि, यहाँ मामला नहीं है विचाराधीन बाज़ार समिति को स्थानीय निधि का नियंत्रण सौंपा गया था और इसलिए। किसी भी कारण से यह मानना असंभव है कि सोसायटी "स्थानीय सरकारी इकाई" के रूप में कार्य कर रही है या यह किसी भी फंड को नियंत्रित या प्रबंधित करती है जो उपलब्ध है और जिसका उपयोग ऐसी इकाई के मामलों के प्रशासन के उद्देश्य से किया जाना है।

(26) ***बी इन भिखारी बेहरा बनाम एस.एम. धनपति बेंटिया (14)(सुप्रा)*** मुद्दा यह उठा कि क्या, कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड का एक कर्मचारी, जो एक क़ानून के तहत बनाया गया था, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के नियम 48 के उप-नियम (1) के अर्थ के तहत एक स्थानीय प्राधिकारी का नौकर था। यह पाया गया कि बोर्ड के धन का मूल भाग पंजीकृत नियोक्ताओं द्वारा आपूर्ति किया गया था, जिन पर क़ानून के आदेश के तहत एक उपयुक्त लेवी लगाई गई थी। बिजयेश मुखर्जी, न्यायाधीश, जिन्होंने मामले का फैसला किया, ने माना कि फंड एक स्थानीय फंड था, जिस पर कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड कानूनी रूप से हकदार था और यहां तक कि नियंत्रण और प्रबंधन के लिए क़ानून के आदेश के तहत राज्य द्वारा सौंपा गया था और इसलिए बोर्ड एक

[14] A.I.R. 1970 Cal. 176.

स्थानीय प्राधिकारी था। मामला दो पहलुओं से अलग है। सबसे पहले, बोर्ड, जैसा कि पहले ही कहा गया है, एक क़ानून का निर्माण था जो सोसायटी नहीं है। दूसरे, फंड एक वैधानिक लेवी का परिणाम थे और इसलिए, इसे किसी विशेष उद्देश्य के लिए क़ानून द्वारा लगाया गया कर माना जा सकता है, जबकि सोसायटी के पास कोई लेवी लगाने की शक्ति नहीं है।

(27) बताए गए कारणों से, मेरा मानना है कि सोसायटी को उप-धारा (5) के खंड (जी) के अर्थ के भीतर न तो स्थानीय प्राधिकारी माना जा सकता है और न ही याचिकाकर्ता को स्थानीय प्राधिकारी का पूर्णकालिक वेतनभोगी सेवक माना जा सकता है। पंचायत अधिनियम की धारा 6 उनके नामांकन पत्र की अस्वीकृति अवैधता से प्रभावित है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। तदनुसार, आक्षेपित आदेश (याचिका का अनुबंध "बी") चुनाव के साथ रद्द किया जाता है, जो याचिकाकर्ता को इसमें भाग लेने का अवसर दिए बिना पाया गया था। मामले की परिस्थितियों में पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सृष्टि
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
कुरूक्षेत्र, हरियाणा